

## वदिश व्यापार नीति 2023

### प्रलिस के लयि:

वदिश व्यापार नीति 2023 के प्रमुख घटक, पीएम-मतिर (MITRA)

### मेन्स के लयि:

वदिश व्यापार नीति 2023, वगित व्यापार नीतियों के साथ तुलना ।

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय वाणजिय एवं उद्योग तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वतिरण मंत्री ने वदिश व्यापार नीति (FTP) 2023 लॉन्च की, जो 1 अप्रैल, 2023 से लागू हुई ।

- FTP 2023 एक नीति दस्तावेज़ है जो नरियात को सुगम बनाने वाली समय-परीक्षणति योजनाओं (Time-tested schemes facilitating exports) की नरितरता पर आधारति है, साथ ही यह एक ऐसा दस्तावेज़ है जो त्वरति व्यापार आवश्यकताओं के लयि उत्तरदायी है ।

## FTP 2023 का वविरण:

- परचिय:**
  - यह नीति नरियातकों के साथ वशिवास एवं साझेदारी के सदिधांतों पर आधारति है और इसका उद्देश्य नरियातकों को व्यापार करने में आसानी की सुवधि हेतु पुनः इंजीनयिरगि तथा स्वचालन (Re-Engineering and Automation) की प्रक्रया से है ।
- मुख्य दृष्टिकोण चार सतंभों पर आधारति है:**
  - छूट के लयि प्रोत्साहन ।
  - सहयोग के माध्यम से नरियात संवर्द्धन - नरियातक, राज्य, ज़िले, भारतीय मशिन ।
  - व्यापार करने में सुगमता, लेन-देन की लागत में कमी और ई-पहल ।
  - उभरते क्षेत्र- **ई-कॉमर्स** नरियात हब के रूप में ज़िलों का वकिस करना एवं वशिष रसायन, जीव, सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी (SCOMET) नीति को सुवयवस्थति करना ।
- लक्ष्य:**
  - सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक भारत के समग्र नरियात को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है, जसिमें वस्तु एवं सेवा क्षेत्रों का समान योगदान होगा ।
  - सरकार का लक्ष्य **सीमा पार व्यापार में भारतीय मुद्रा के उपयोग** को प्रोत्साहति करना भी है, जो जुलाई 2022 में RBI द्वारा पेश कयि गए एक नए भुगतान नपिटान ढाँचे से सहायता प्राप्त है ।
  - यह उन देशों के मामले में वशिष रूप से फायदेमंद हो सकता है जनिके साथ **भारत व्यापार अधशिष की स्थिति** में है ।

## FTP 2023 की मुख्य या महत्त्वपूरण वशिषताएँ:

# SALIENT FEATURES

▶ Targets **\$2 trillion** exports by 2030

▶ Continuous and responsive framework with no end date

▶ Making rupee a global currency

▶ Making India a trade hub

▶ Digitisation and faster processing of applications

▶ Amnesty scheme for shortfall in export obligations

▶ Restructuring of Department of Commerce

▶ Over 50% reduction in threshold for recognition of star trade houses

## ■ पुनः इंजीनियरिंग प्रक्रिया और स्वचालन:

- यह नीति नरियात संवर्द्धन और विकास को प्रोत्साहन आधारित व्यवस्था से एक ऐसी व्यवस्था में परिवर्तित करने पर बल देती है जो प्रौद्योगिकी इंटरफेस एवं सहयोग के सिद्धांतों के आधार पर सुविधा प्रदान करती है।
- **शुल्क संरचनाओं** और **IT-आधारित योजनाओं** में कमी से MSME तथा अन्य के लिये नरियात लाभ प्राप्त करना आसान हो जाएगा।
- नरियात उत्पादन के लिये शुल्क छूट योजनाएँ अब कषेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से एक नयिम-आधारित IT प्रणाली के वातावरण में कार्यान्वयित की जाएंगी, जिससे मैन्युअल इंटरफेस की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।

## ■ नरियात उत्कृष्टता वाले शहर (TEE):

- मौजूदा 39 शहरों के अलावा चार नए शहरों, अर्थात् **फरीदाबाद, मरिजापुर, मुरादाबाद और वाराणसी** को TEE के रूप में नामित किया गया है।
- TEEs को MAI योजना के तहत नरियात संवर्द्धन नधियों तक पहुँच प्राप्त होगी और **वेनरियात संवर्द्धन पूंजीगत वस्तु (EPCG) योजना** के तहत नरियात पूरति हेतु **सामान्य सेवा प्रदाता (CSP)** लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

## ■ नरियातकों को मान्यता:

- नरियात प्रदर्शन के आधार पर 'स्थिति' के साथ मान्यता प्राप्त नरियातक फर्मों अब सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर कषमता नरिमाण पहल में भागीदार होंगी।
- **'ईच वन टीच वन' (Each One Teach One) पहल के समान, 2-स्टार और उससे ऊपर की स्थितिधारकों को** इच्छुक व्यक्तियों को एक मॉडल पाठ्यक्रम के आधार पर व्यापार से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।
- स्थितिमान्यता मानदंडों को पुनः नरिधारित किया गया है ताकि अधिक नरियातक फर्मों को **4 और 5-स्टार रेटिंग** हासिल करने में सक्षम बनाया जा सके, जिससे नरियात बाजारों में बेहतर ब्रांडिंग के अवसर पैदा हो सकें।

## ■ ज़िलों से नरियात को बढ़ावा देना:

- FTP का उद्देश्य राज्य सरकारों के साथ साझेदारी का नरिमाण करना और ज़िला स्तर पर नरियात को बढ़ावा देने तथा ज़मीनी स्तर पर व्यापार पारस्थितिकी तंत्र के विकास में तेज़ी लाने हेतु **ज़िलों को नरियात हब (DEH) पहल** के रूप में आगे ले जाना है।
- नरियात योग्य उत्पादों एवं सेवाओं की पहचान करने और ज़िला स्तर पर समस्याओं को हल करने का प्रयास क्रमशः राज्य और ज़िला स्तर पर एक संस्थागत तंत्र - राज्य नरियात प्रोत्साहन समिति और ज़िला नरियात प्रोत्साहन समिति के माध्यम से किया जाएगा।
- पहचान किये गए उत्पादों और सेवाओं के नरियात को बढ़ावा देने हेतु ज़िला वशिष्ट रणनीतिको रेखांकित करते हुए **प्रत्येक ज़िले के लिये ज़िला वशिष्ट नरियात कार्ययोजना** तैयार की जाएगी।

## ■ SCOMET नीति को कारगर बनाना:

- भारत **"नरियात नयित्रण" व्यवस्था पर अधिक ज़ोर दे रहा है क्योंकि नरियात नयित्रण व्यवस्था वाले देशों** के साथ यह मज़बूत व्यापार एकीकरण सुनिश्चित कर रहा है।
- SCOMET पर हतिधारकों के बीच व्यापक पहुँच और समझ है, साथ ही भारत द्वारा की गई अंतरराष्ट्रीय संधियों एवं समझौतों को लागू करने हेतु नीतिव्यवस्था को और अधिक मज़बूत बनाया जा रहा है।
- भारत में मज़बूत नरियात नयित्रण प्रणाली भारत से **SCOMET के तहत नयित्रण वस्तुओं/प्रौद्योगिकियों के नरियात की सुविधा प्रदान करते हुए भारतीय नरियातकों को दोहरे उपयोग वाली कीमती वस्तुओं** और प्रौद्योगिकियों तक पहुँच प्रदान करेगी।

## ■ ई-कॉमर्स नरियात को सुगम बनाना:

- वर्ष **2030 तक ई-कॉमर्स कषेत्र में नरियात की संभावना 200 से 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर** के बीच होने का अनुमान है।
- FTP 2023 में भुगतान समाधान, बहीखाता पद्धति, वापसी नीति और नरियात पात्रता जैसे संबंधित घटकों के साथ-साथ **ई-कॉमर्स केंद्र** बनाने का लक्ष्य और रोडमैप शामिल है।

- FTP 2023 में शुरुआती बट्टि के रूप में कूरयिर-आधारति ई-कॉमर्स नरियात हेतु खेप-आधारति सीमा को 5लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है।
- नरियातकों की प्रतक्रिया के आधार पर इस सीमा को संशोधति कथि जाएगा या अंततः हटा दिया जाएगा।
- **EPCG योजना के तहत सुवधि:**
  - EPCG योजना जो नरियात उत्पादन हेतु शून्य सीमा शुल्क पर पूंजीगत वस्तुओं के आयात की अनुमति देती है, को और अधिक युक्तसंगत बनाया जा रहा है। शामिल कुछ प्रमुख परिवर्तन हैं:
    - **प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र कषेत्र और परधान पार्क (Prime Minister Mega Integrated Textile Region and Apparel Park- PM MITRA) योजना** को EPCG की सामान्य सेवा प्रदाता (Common Service Provider- CSP) योजना के तहत लाभ हेतु पात्र अतरिक्रित योजना के रूप में जोड़ा गया है।
    - डेयरी कषेत्र को प्रौद्योगिकी के उन्नयन हेतु डेयरी कषेत्र का सहयोग करने के लथि औसत नरियात दायतित्व बनाए रखने से छूट दी जाएगी।
    - सभी प्रकार के **बैटरी चालति इलेक्ट्रिक वाहन**, वर्टकिल फार्मगि उपकरण, अपशषिट जल उपचार और पुनर्रचकरण प्रणाली, वर्षा जल संचयन प्रणाली, वर्षा जल फल्टर तथा ग्रीन हाइड्रोजन को हरति प्रौद्योगिकी उत्पादों की सूची में जोड़ा गया है जो EPCG योजना के तहत अब कम नरियात दायतित्व आवश्यकता हेतु पात्र हैं।
- **अग्रमि प्राधकिरण योजना के तहत सुवधि:**
  - घरेलू टैरफि कषेत्र (DTA) इकाइयों द्वारा उपयोग की जाने वाली अग्रमि प्राधकिरण योजनानरियात वस्तुओं के नरिमाण के लथि कच्चे माल पर शुल्क मुक्त आयात की सुवधि प्रदान करती है और इसे EOU तथा SEZ योजना के समान स्तर पर रखा गया है।
  - नरियात आदेशों के त्वरति नषिपादन की सुवधि के लथि स्व-घोषणा के आधार परपरधान और वस्त्र कषेत्र के नरियात के लथि विशेष अग्रमि प्राधकिरण योजना का वसितार कथि गया।
  - इनपुट-आउटपुट मानदंड तय करने के लथि स्व-अनुमान योजना के लाभ वर्तमान में अधिकृत आर्थिक ऑपरेटरो के अतरिक्रित 2 स्टार और उससे अधिक की श्रेणी वाले धारकों के लथि वसितारति कथि गए हैं।
- **एमनेस्टी योजना:**
  - **एमनेस्टी योजना के तहत पंजीकरण के लथि एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कथि जाएगा** और नरियातकों को इस योजना का लाभ उठाने के लथि छह महीने की वडिो उपलब्ध होगी।
  - इसमें प्राधकिरणों के नरियात दायतित्व में चूक से संबंधति सभी लंबति मामले शामिल होंगे, इन्हेंअपूर्ण नरियात दायतित्व के अनुपात में छूट प्राप्त सभी सीमा शुल्क के भुगतान पर नथिमति कथि जा सकता है।

## पछिली व्यापार नीति:

- वर्ष 2015-2020 के लथि वदिश व्यापार नीति में वर्ष 2020 तक 900 बलियिन अमेरिकी डॉलर के नरियात का लक्ष्य रखा गया था;
- इस नीति और लक्ष्य को बढ़ाकर मार्च 2023 तक कर दिया गया था।
  - हालाँकि भारत द्वारा वर्ष 2021-22 के 676 बलियिन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले वर्ष 2022-23 की समाप्तपर 760-770 बलियिन अमेरिकी डॉलर का कुल नरियात कथि जाने की संभावना है

स्रोत: पी.आई.बी.